(ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के विभिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों के संबंध में हुए कार्य की समीक्षा की जा रही है ताकि इस नीति में निर्धारित लक्ष्य सन 2000 ईस्वी तक प्राप्त किए जा सकें।

देश में जहरीली और मिलावटी शराब के कारण हुई मौतें

4173. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान जहरीली और मिलावटी शराब पीने के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए अन्धे हो गए और अन्य प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर कार्य करने के लिए अयोग्य हो गए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) इस मिलावटी और जहरीली शराब में राज्यवार किन-किन तत्वों की मिलावट पायी गयी ;

(ग) जहरीली और मिलावटी शराब बनाने और बेचने का अबैध व्यापार करने के संबंध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और न्यायालयों द्वारा दंडित किए गए व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं ; और

(घ) इस प्रकार की अकाल मृत्यु को रोकने के लिए सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० शईद) : (क) और (ख) जहरीली शराब और मिलावटी औषधियों और दवाओं का सेवने करने से वर्ष 1990, 1991 और 1992 के दौरान सूचित हुई राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार हुई मौतों के उपलब्ध आकडे का विवरण अनुपत्र में दिया गया है [देखिए परिशिष्ट 166, अनुपत्र संख्या 67] अंधे हो गए अथवा अन्य बीमारियों से ग्रस्त पीडितों, जिसके कारण कार्य करने आदि के लिए अयोग्य हो गए व्यक्तियों के बारे में अलग से सूचना तथा जहरीली और मिलावटी शराब में प्रयोग किए गए अन्य घटकों के ब्यौरे की सूचना के राज्यवार ब्यौरे केंद्रीय एजेसियों द्वारा संकलित किए जाते हैं ।

(ग) और (घ) अबैध शराब की बिक्री और निर्माण सहित, अपराधों को दर्ज करना, उनकी जाच पडताल करना; उनका पता लगाना तथा उसकी रोकथाम करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है । न्यायालयों द्वारा दंडित किए गए व्यक्तियों के बारे में आंकडे, केन्द्र सरकार की एजेंसियों द्वारा नहीं रखे जाते हैं । तथापि, अवैध शराब का उत्पादन एवं उसकी बिक्री को ररोकने के लिए और साथ ही शराब में मिलावट के लिए घातक पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण के लिए सरकार ने दिनांक 14 नवम्बर, 1991 को सभी राज्य औषध नियंत्रणों को निर्देश जारी किए हैं कि वे प्राथमिकता के आधार पर सभी निर्माता फर्मो का निरीक्षण करें । "पलसन्ना" के अधीन पर शोधित स्प्रिट के प्रयोग को अनुमति वापस ले ली गई है । आयुर्वेदिक दवाई के रूप में नकली शराब बेचे जाने की सम्भावना को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 2 दिसम्बर, 1992 को एक अधिसूचना जारी की है ।

परिवार कल्याण केन्द्रों को बन्द किया जाना

4174. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठ मलानी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 दिसम्बर, 1992 के दैनिक समाचार-पत्र "पॉयनियर" में "गवर्मेंट में वाईड-अप फैमिली वैलफेयर सैंटर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ परिवार कल्याण केन्द्रों को बन्द करने का निर्णय ले लिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह भी सच है कि परिवार कल्याण हेतु दिसम्बर, 1992 तक राज्य सरकारों को देय एक बड़ी धन राशि सरकार पर बकाया है ; और

(घ) यदि हां, तो कुल धन-राशि कितनी थी और बकाया राशि का अब तक भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) 1992-93 के दौरान राज्य सरकारों को अंकेक्षित व्यय विवरण के आधार पर 301.48 करोड़ रुपए की बकाया राशि में से 100.00 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई है। 1993-94 के दौरान और राशि रिलीज की जायेगी।

स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों का विनियमन

4175. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि 1 अगस्त, 1990 से पूर्व स्थापित सभी स्वास्थ्य-प्रतिष्ठानों को नियमित कर दिया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे प्रतिष्ठानों की संख्या का पता लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने प्रतिष्ठान हैं और इन्हें नियमित करने संबंधी निर्णय के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पहली अगस्त, 1990 से पहले खुले उपचर्या गृहों को अपेक्षित शुल्क के भुगतान पर 1996 तक जारी रखने की अनुमति देने का निर्णय सिद्धांत रूप में लिया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उपचर्या गृहों की उपयुक्तता के निर्धारण संबंधी सर्वेक्षण पूरा हो गया है अब उन्हें नियमित करने के प्रश्न पर दिल्ली विकास प्राधिकरण से परामर्श किया जा रहा है जो भूमि के इस्तेमाल की अनरूपता जैसे विषयों का निर्धारण करता है।

Medical facilities in Rural Areas

4176. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what is the amount of money spent by Government in improving medical facilities in rural areas in the country during the last two years; and

(b) what is the amount of money Government propose to spend during the current year in rural areas?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) The amount released by the Department of Family Welfare for implementation of different schemes in rural areas during the last two years is given below:—

(Rs. in crores)

Year	Amount
1990-91	339.97
1991-92	451.93